(b) what steps the Union Territory Administration have taken or propose to take for revising the orders of those Lecturers whose placement in the Senior scale and selection grade w.e.f. 1st January, 1986 vis-a-vis their junior on the basis of seniority goes against the clarification of Government of India contained in letter No. 4-20/92-UT-I dated 10th May, 1993;

(c) the number and details of such cases referred in part (a) and (b) above; and

(d) by when the corrective steps are likely to be taken ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्त का पद

3424. **श्री रामदेव भंडारी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्त के 18 पद हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति सहायक आयुक्त के पदों पर हुई हैं ;

(ग) क्या ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है ;

(घ) क्या जनवरी, 1994 में चार सहायक आयुक्तों की नियुक्ति की गई है ;

(ङ) क्या इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किन्हीं उम्मीदवारों की भी नियुक्ति हुई है ;

(च) इस आरक्षण कोटे के पूरे न किए जाने के कारण क्या-क्या हैं ;

(छ) क्या सरकार शीघ्र ही आरक्षण कोटा पूरा करेगी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय अनुसूचित जातियों के 4 सहायक आयुक्त और अनुसूचित जनजाति श्रेणी का एक सहायक आयुक्त है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (ज) दिसम्बर, 1993–जनवरी, 1994 के दौरान, 4 सहायक आयुक्त (3 साधारण कोटि के तथा 1 अनुसूचित जाति कोटि का) नियुक्त किए गए थे। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद नहीं भरा जा सका क्योंकि पात्र अभ्यार्थियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और रिक्त पद को नियमानुसार, संगठन द्वारा पुनः विज्ञाप्ति किया जाएगा :

राष्ट्रीय पुस्तक नीति का लागू किया जाना

3425. **श्रीमती सरला माहेश्वरी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक नीति को लागू किए जाने के उद्देश्य क्या-क्या थे,

(ख) इस नीति का अब तक लेखकों, पाठकों और प्रकाशकों पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या इस संबंध में कोई समीक्षा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस प्रकार की किसी समीक्षा की कोई आवश्यकता समझी जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा

नीति–1986 (1992 में यथासंशोधित) में कम मूल्यों पर पुस्तकों की उपलब्धता, जनता के सभी वर्गों के लिए पुस्तकों की सुगम सुलभता: पुस्तकों की कोटि में सुधार, पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में पाठ्य पुस्तकों और अभ्यसा पुस्तकों सहित बच्चों के लिए कोटिपरक पुस्तकें तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है ।

(ख) से (घ) इस स्तर पर नीति की काई भी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपनी उचित मूल्यों वाली पुस्तकों का अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों में उत्पादन बढ़ाने, वाचनालय क्लबों की स्थापना करके स्कूल स्तर पर पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने, भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट पुस्तकों के अनुवाद को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र स्थापित करने इत्यादि के लिए अनेक उपाए किए हैं।

Eradication of Illiteracy

3426. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to eradicate illiteracy from the country before the end of the present century;

(b) if so, whether the total literacy campaign which is currently on is considered adequate for the purpose:

(c) the measures taken to ensure that neo-literates under the total literacy campaign do not lapse into illiteracy; and

(d) the total annual outlay proposed for each of the next five years for eradication of illiteracy?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) As enshrined in the Delhi Declaration of 16th December, 1993 the Government proposes to ensure, by the year 2000 or at the earliest possible moment, a place for every child in a school or appropriate education programe according to his or her capabilities. The Total Literacy Campaigns cater to primarily the age group of 15—35. Through this strategy the entire illiterate population in this age group is proposed to be covered. Universalisation of Elementary Education, Non-formal Education for School Drop-outs and the Adult Education Programmes under the National Literacy Mission constitute the three pronged strategy to eradicate illiteracy from the country.

(c) Each Total Literacy Compaign is followed by a Post Literacy Compaign to ensure that the neo-literates do not relapse into illiteracy. Apart from the Post Literacy Campaigns, there is also a Centrally Sponsored Scheme of Post Literacy and Continuing Education under which institutionalised arrangements have been made through the setting up of Jana Shikshan Nilayams.

(d) During the 8th plan an allocation of Rs. 1,400 crores has been made Adult Education and Rs. 2,880 crores under Elementary Education.

मध्य प्रदेश में रानीताल में युवा होस्टल का निर्माण

3427. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर के रानीताल में युवा होस्टल के निर्माण के लिए 15 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त होस्टल भवन का नक्शा स्वीकृत किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?